सामाजिक नीति निर्माण की प्रक्रिया, अनुसंधान का योगदान तथा हित समूहों की भूमिका को

परिचय

सामाजिक नीति (Social Policy) वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय, समानता एवं मानव विकास के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करती है। किसी भी सामाजिक नीति का निर्माण एक वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक एवं सहभागी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सरकार, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन (NGO), विशेषज्ञ तथा विभिन्न हित समूह (Interest Groups) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. सामाजिक नीति निर्माण की प्रक्रिया (Process of Social Policy Formulation)

सामाजिक नीति का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है—

(1) सामाजिक समस्या की पहचान

समाज में विद्यमान समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।

समस्याओं की गंभीरता एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।

उदाहरण: गरीबी, बेरोजगारी, बाल श्रम, महिला हिंसा, कुपोषण आदि।

(2) सूचना एवं आँकड़ों का संकलन

जनगणना, सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं सरकारी रिपोर्टों से तथ्य एकत्र किए जाते हैं।

विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर नीति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है।

(3) उद्देश्य निर्धारण

नीति के स्पष्ट एवं यथार्थ उद्देश्य तय किए जाते हैं।

उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं एवं संविधान के मूल्यों के अनुरूप होते हैं।

(4) विकल्पों का निर्माण

समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्प तैयार किए जाते हैं।

प्रत्येक विकल्प के लाभ, लागत एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

(5) परामर्श एवं विचार-विमर्श

विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों, हित समूहों एवं गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव लिए जाते हैं।

इससे नीति अधिक व्यावहारिक एवं जनहितकारी बनती है।

(6) नीति का निर्माण एवं अनुमोदन

सरकार नीति का प्रारूप तैयार करती है।

आवश्यक होने पर मंत्रिमंडल एवं संसद/विधानसभा से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

(7) क्रियान्वयन (Implementation)

संबंधित विभाग एवं संस्थाएँ नीति को लागू करती हैं।

योजनाएँ, कार्यक्रम एवं बजट निर्धारित किए जाते हैं।

(8) मूल्यांकन एवं संशोधन

नीति के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है।

आवश्यकतानुसार संशोधन एवं सुधार किए जाते हैं।

2. सामाजिक नीति निर्माण में अनुसंधान का योगदान (Contribution of Research)

अनुसंधान (Research) सामाजिक नीति निर्माण का वैज्ञानिक आधार है। यह नीति को तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित बनाता है।

अनुसंधान का योगदान

(1) समस्या की सही पहचान

अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करता है।

(2) तथ्य एवं आँकड़े उपलब्ध कराना

विश्वसनीय आँकड़े नीति निर्माण को सटीक एवं प्रभावी बनाते हैं।

(3) नीति निर्माण में सहायता

अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त नीति बनाई जाती है।

(4) भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान

बदलती सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है।

(5) नीति का मूल्यांकन

अनुसंधान से यह पता चलता है कि नीति कितनी सफल रही।

(6) संसाधनों का उचित उपयोग

अनुसंधान यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार हो।

(7) नवाचार एवं सुधार

अनुसंधान नई तकनीकों एवं बेहतर उपायों का सुझाव देता है।

3. सामाजिक नीति निर्माण में हित समूहों (Interest Groups) की भूमिका

अर्थ

हित समूह वे संगठन या समूह होते हैं जो किसी विशेष वर्ग या समुदाय के हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए सरकार को सुझाव, समर्थन या दबाव प्रदान करते हैं।

उदाहरण: किसान संगठन, श्रमिक संगठन, महिला संगठन, व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ (NGO), उपभोक्ता संगठन आदि।

हित समूहों की भूमिका

(1) समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना

समाज की वास्तविक समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

(2) नीति निर्माण में सुझाव देना

विशेषज्ञ राय एवं व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराते हैं।

(3) जनमत तैयार करना

जनता में जागरूकता फैलाते हैं तथा नीति के पक्ष या विपक्ष में जनमत तैयार करते हैं।

(4) कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, किसानों, श्रमिकों एवं वंचित वर्गों की आवाज़ बनते हैं।

(5) नीति के क्रियान्वयन में सहयोग

सरकार के साथ मिलकर योजनाओं के प्रभावी संचालन में सहयोग करते हैं।

(6) निगरानी एवं मूल्यांकन

नीति के प्रभाव एवं कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

(7) लोकतंत्र को सशक्त बनाना

नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं।

सामाजिक नीति निर्माण में अनुसंधान एवं हित समूहों का महत्व

नीति को वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित बनाते हैं।

वास्तविक समस्याओं की पहचान होती है।

नीति अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बनती है।

जनसहभागिता एवं पारदर्शिता बढ़ती है।

सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

नीति की सफलता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

सामाजिक नीति निर्माण एक सतत एवं सहभागी प्रक्रिया है। इसमें अनुसंधान नीति को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जबकि हित समूह समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को सरकार तक पहुँचाते हैं। दोनों के समन्वित प्रयासों से ऐसी सामाजिक नीतियाँ बनती हैं जो सामाजिक न्याय, समानता, मानव गरिमा तथा समावेशी विकास के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. Friedlander, Walter A. (1977). Concepts and Methods of Social Work. Prentice Hall of India.

2. Kulkarni, P. D. (1979). Social Policy and Social Development in India. Association of Schools of Social Work in India.

3. Titmuss, Richard M. (1974). Social Policy: An Introduction. George Allen & Unwin.

4. Dubey, S. N. (2015). Social Work: An Integrated Approach. New Royal Book Company.

5. गोयल, एस. एल. एवं गोयल, राकेश. (2018). सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक नीति. आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

6. सिंह, आर. बी. एस. (2016). समाज कार्य एवं सामाजिक नीति. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।